[Shri N. Selvaraju]

Power Station and Refinery, additional movement of traffic and custom is fast building up.

(v) The Indian Navy will have the advantage of moving from Palk Straits into the Gulf of Manner without having to cruise through international waters.

(vi) There are ample possibilities to develop the hinterland which will increase the potential economic benefits.

I, therefore, request the Government of India to come forward to take up the project for implementation n the best interest of the nation without any more delay as it will push up the project cost.

(viii) Power crisis in Uttar Pradesh and need for supply of additional power to the State.

15. hrs.

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह (सम्भल) : उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में आई भारी गिरावट के कारण किसानों को रबी की बुवाई व फसल की सिंचाई के समय ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली नहीं के बराबर मिल पा रही है। जितनी बिजली मिल रही है वह भी लगातार प्राप्त नहीं होने से ट्यूबवैल बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। खास कर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्भल में। क्योंकि निर्धारित समय में भी बिजली बीच-बीच में चले जाने से ट्यूबवैल का पानी खेत तक नहीं पहुंचता है, गूल में ही रह जाता है।

किसान इस स्थिति से बहुत परेशान है। यह पलेवा व फसल की सिंचाई करने का समय है। उत्तर प्रदेश सरकार का कथन है कि ओबरा ताप विद्युत गृह के जल जाने के कारण विद्युत उत्पादन में जो कमी आई है, केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय उसकी पूर्ति नहीं कर रहा है।

अत: उर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि तत्काल उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत प्रदान करें ताकि किसान की रबी की बुवाई व फसल की सिंचाई के वक्त ट्यूबवैल के लिए आवश्यक विद्युत प्राप्त हो सके।

(ix) Need for redressing the grievances of Loco Running Staff.

SHRI BASUDEB ACHARYA (Bankura) : All India Loco Running Staff Association is organising a demonstration today at the Boat Club with the intention to represent their grievances before the Railway Minister. The Railway Administration has taken all measures in order to see that the workers cannot participate in the demonstration. Their own leave and passes were denied and they were being threatened with dire consequences.

The Loco Running Staff of Indian Railways are striving since long for redressal of their demands but they are being repressed and victimised and their problems remain unresolved. Their existing facilities have been curtailed and promotional policy has been changed. They are being forced to work for more than ten hours and are to work with sick rolling stock and engines. The active workers of their Association are under severe attack and are penalised and transferred for any trade union activity.

The convention of ILO decided to bring duty hours of workers to 8 hours. Further, Inland Transport Committee under ILO decided that the duty hours of the workers should be brought to 40 hours a week. In both cases, the Government of India was a party to the

decision But in the Railways the Loco Running Staff and Running Staff as a whole have been forced to work any number of hours even upto the extent of 18/20 hours.

The agreement arrived with All India Loco Running Staff Association for 10 hours duty from signing on to signing off in the year 1973 and announced on the floor of Parliament by the then Minister of Railways, late L.N. Mishra, has not been honoured.

I urge upon the Government to take steps to redress the grievances of Loco Running Staff and Indian Railways.

15.05 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* DISAPPROVAL OF TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1983—CONTD.

AND

TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Now we take up further discussion on the statutory resolution moved by Shri Satyanarayan Jatiya. You have already taken 10 minutes. Please wind up.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मेरी पार्टी के कारण मुझे मौका नहीं मिला है।

सभापति महोदय : पार्टी को टाईम का अलाटमेंट होता है इसलिए इसके मुताबिक दस मिनट भी ज्यादा है। ज्यादा टाईम नहीं मिलेगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं महत्वपूर्ण विषय पर जिसका अध्यादेश जारी हुआ था, उसके निरनुमोदन पर खड़ा हुआ हूं। यह डिस्क्रीशन की बात नहीं है कि यहां क्या निर्णय लिया जायेगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा था कि 13 मिलों का अधिग्रहण हुआ है। उस अधिग्रहण के पीछे जो सरकार की नीति और नियत है, वह प्रकट होती है। मिलों का जो अधिग्रहण कर रहे हैं, उनका प्रबन्ध अधिग्रहण पहली शुरुआत है। उसके बाद राष्ट्रीयकरण की बात की जाएगी।

मिलों का जो अधिग्रहण को रहा है, उसमें ध्यान दिया गया है कि लोगों को बेराजगार होने से बचाया जाए। इन सारी मिलों की देनदारियां बाकी हैं। उन देनदारियों को चुकाने के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है जो देनदारियां इन 17 मिलों की बाकी हैं, उसके बारे में आप बतायें कि किसकी जवाबदेही है। 60 करोड़ रुपया एप्लाइज का इन 17 मिलों द्वारा देना बाकी है जिसमें से 50 करोड़ रुपया रुई सप्लाई करने वालों को बाकी है। उनका क्या गुनाह है कि उनको अपनी रुई का पैसा आज तक नहीं मिला है। अब इन मिलों को सरकार चला रही है। सरकार का नैतिक दायित्व है कि इन देनदारियों को चुकाए। पिछली बार 112 मिलें एन० टी० सी० के अन्तर्गत लाई गई थीं। उन मिलों का देनदारियां आज तक चुकाई नहीं गई हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिये। यह दोष उन लोगों का नहीं है जिन्होंने माल सप्लाई किया है। यह ठीक है कि ये मिलें किसी